

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: आलोचनात्मक विश्लेषण

सपना सैनी

शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. (डॉ.) मंजू शर्मा

शोध निर्देशिका, फैकल्टी ऑफ एज्यूकेशन एण्ड मैथडोलॉजी

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 भाग और 27 अध्याय हैं। नीति में, भारत सरकार ने बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाली विभिन्न बाधाओं और स्थितियों का वर्णन तैयार किया। यह परिचय के साथ शुरू होता है जिसमें बच्चों की मूलभूत आवश्यकता, मानव क्षमता को कैसे प्राप्त किया जाए, समानता का विकास और समाज में न्याय, राष्ट्रीय विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में बताया गया है। यह 2030 में भारत द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडे के लक्ष्यों का भी वर्णन करता है। इन लक्ष्यों समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है और 2030 तक सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। नीति तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा करती है जो महत्वपूर्णता हैं। भारत का लक्ष्य 2040 तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना भी है। नीति को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है— भाग 1— स्कूली शिक्षा, भाग 2— उच्च शिक्षा, भाग— 3 व्यावसायिक शिक्षा, और अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र, भाग— 4 विभिन्न शिक्षा बोर्डों को मजबूत बनाना और वित्त पोषण करना, आदि।

एनईपी 2020 के अंतर्गत परिवर्तन

1968 और 1986 की शिक्षा नीति के बाद NEP 2020 नई नीति है जिसका उद्देश्य शिक्षक की गुणवत्ता के साथ-साथ छात्र की गुणवत्ता में सुधार करना है। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ज्ञान के साथ छात्रों का सशक्तिकरण करना है। इस 2020 एनईपी नीति में सरकार ने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बदल दिया था। नई व्यवस्था में 10 नए महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं।

NEP 2020 नीति में मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं

1. स्कूली शिक्षा 3 साल की उम्र से आंगनवाड़ी या किंडर गार्डन के रूप में शुरू होती है।
2. शिक्षा का ढांचा 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया था।

3. विज्ञान, कला और वाणिज्य के बीच भेदभाव और कठोरता को हटा दिया गया था।
4. इंटरनशिप और व्यावसायिक शिक्षा की योजनाएं कक्षा 6 से शुरू की गई थीं। यह छात्र को काम के माहौल के बारे में स्पष्टता और अनुभव प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है साथ ही उन्हें अपने सामाजिक कौशल के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान में सुधार करने में भी मदद करता है।
5. एनईपी ने बोर्ड परीक्षा के मॉडल में बदलाव लाया था। हालांकि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जारी है, परीक्षा के मॉडल को बदल दिया गया है और परीक्षा पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं होगी, यह मुख्य विषय ज्ञान के मूल्यांकन पर केंद्रित होगी।
6. एनईपी 2020 ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम प्रणाली को वापस लाया था।
7. प्रमुख सुधार 2035 तक सकल नामांकन अनुपात के 50: को लक्षित कर रहे थे।
8. कॉमन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के सभी रूपों में आयोजित किया जाएगा।
9. कॉलेज की फीस सरकार द्वारा तय की जाएगी और कॉलेज की फीस की निगरानी के लिए एक अलग समिति का गठन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कॉलेज निर्धारित कैप से ऊपर कोई फीस न वसूले।
10. एमफिल कार्यक्रम को शिक्षा ढांचे से हटाकर शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा माध्यम की शुरुआत की जाएगी।

यह संशोधित नीति अनिवार्य शिक्षा की अवधि को 6–14 वर्ष से बढ़ाकर 3–18 वर्ष कर देती है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना भी है। नई प्रणाली में 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री-स्कूलिंग शामिल है। नई शैक्षणिक संरचना में निम्नलिखित वर्गीकरण शामिल हैं।

1. फाउंडेशन स्टेज— आंगनवाड़ी या प्री-स्कूल शिक्षा और कक्षा 1 और 2 प्रणाली में 3 से 8 वर्ष की आयु तक 5 वर्ष। इस प्रणाली में केवल बहु-स्तरीय खेल गतिविधि, इंटरैक्टिव स्कूल गतिविधि और साहित्य और अंकों की बुनियादी शिक्षा है।
2. प्रारंभिक चरण— 8 से 11 वर्ष की आयु तक 3 वर्ष। इस चरण में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक शामिल है। इस प्रणाली में सभी विषयों और उनकी गतिविधियों की बुनियादी शिक्षा शामिल होगी।
3. मध्य चरण— 11 से 14 वर्ष की आयु तक 3 वर्ष। इस चरण में कक्षा 6— कक्षा 8 शामिल है। इस प्रणाली में कला, सामाजिक गतिविधियों, मानविकी, विज्ञान और गणित की व्यावहारिक शिक्षा शामिल है, जिसमें काम के माहौल का अनुभव करने के लिए संबंधित इंटरनशिप शामिल हैं। वर्णित फील्ड।

4. माध्यमिक चरण— 14 से 18 वर्ष की आयु तक 4 वर्ष। इस चरण में कक्षा 9— कक्षा 12 शामिल है। इस प्रणाली में बहु-विषयक शिक्षा, महत्वपूर्ण विश्लेषण और सोच, छात्रों की पसंद के विषय और उसमें विशेषज्ञता शामिल है।

इसके अलावा, इसके अलावा, यह भी निर्धारित किया गया है कि छात्रों के मूल्यांकन के साथ-साथ छात्रों की उपलब्धि और प्रतिष्ठानों पर नज़र रखने के लिए 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पेश किया जाएगा। यह भी प्रस्तावित है कि शिक्षक शिक्षा 2021 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई जाएगी और शिक्षकों के लिए नई डिग्री योग्यताएं पेश की जाएंगी।

आलोचनात्मक विश्लेषण

नवीन शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में साहित्य, खेल संगीत इत्यादि सम्मिलित किये गये हैं परंतु उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक विषय जिसमें सामान्य ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, मानसिक योग्यता और गणित को लेकर विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं। इससे वही होगा जो होता आ रहा है। 12वीं और कॉलेज शिक्षा के बाद भी विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों की तरफ जाना पड़ेगा।

इस नवीन नीति में बोर्डिंग और डे बोर्डिंग विद्यालयों को लेकर विशेष विकल्प नहीं दिये हैं। यदि बोर्डिंग स्कूलों को लेकर कुछ गुरुकुल पद्धति का समावेश किया जाता तो यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता था। जिसमें 12वीं तक की शिक्षा को बोर्डिंग के माध्यम से ही पूर्ण करवाने पर जोर दिया जाता। इसके लिए विशेष नौकरियों में सुविधाएं दी जा सकती थीं।

नवीन शिक्षा नीति वंचितों, गरीबों और शिक्षा छोड़ देने वालों के लिए उपयुक्त है।

नवीन शिक्षा रोजगार प्राप्ति, विषयों के चयन को लेकर स्वतंत्रता प्रदान करती है परंतु इसके लिए काउंसिलिंग और चयन की समझ के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 4 जून 2021
2. NDTV एजुकेशनल न्यूज,
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
4. नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव